दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित: 18.12.2013
उद्घोषित: 31.01.2014

<u>नि.प्र.अ. (मू.प.) 11/2010, सि.वि.सं. 1950/2010</u>

श्रीमती स्वर्ण लता व अन्य ..... अपीलार्थीगण

द्वारा: श्री सुरेश सिंह व श्री रजनीश चौधरी, अधिवक्तागण

बनाम

श्री कुलभूषण लाल व अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: कोई नहीं

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. रवींद्र भट्ट
माननीय न्यायमूर्ति श्री नज्मी वजीरी

<u>न्यायमूर्ति श्री एस. रवींद्र भट्ट</u>

<u>सि.वि.सं. 1950/2010 (विलंब हेतु माफी)</u>

आवेदन में उल्लिखित कारणों से सि.वि.सं. 1950/2010 को अनुमति किया जाता है।

<u>नि.प्र.अ. (मू.प.) 11/2010</u>

1. यह विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील है, जिसके तहत बहनों द्वारा दायर विभाजन के वाद को खारिज कर दिया गया था। दिनांक 19.04.2012 एवं दिनांक 11.01.2013 के आदेशों से पता चलता है कि पहले तीन प्रत्यर्थीगण (वाद में प्रत्यर्थी पक्षकार) को नोटिस तामिल किया गया था, जिसके बावजूद उन्होंने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी। तदनुसार दिनांक 11.01.2013 के आदेश में दर्ज किया गया कि नोटिस तामिल किया जा चुका था। इन परिस्थितियों में अपील पर अंतिम सुनवाई की गई तथा निर्णय के लिए सुरक्षित रखा गया। इस विभाजन वाद में शामिल संपत्तियों की बारीकियों को संबोधित करने से पूर्व, इस मामले में शामिल पारिवारिक संरचना को दर्ज करना उपयोगी है।

2. वादी, तीन बहनों ने वर्ष 1990 में दो भाइयों (पहले दो प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थी) तथा दो बहनों (तीसरे व चौथे प्रत्यर्थी) के विरूद्ध वाद [सि.वा. (मू.प.) 2400/1990] दायर किया था। एक तीसरे भाई, सुदर्शन लाल की मृत्यु दिनांक 1 फरवरी, 1978 को, संस्थित की शुरुआत से पूर्व, अविवाहित रहते हुए हो गई थी। इस प्रकार परिवार में पाँच बहनें और तीन भाई शामिल थे। उनके पिता बख्शी राम थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 10 फरवरी, 1960 को हुई थी तथा उनकी माँ श्रीमती चनन देवी थीं, जिनकी मृत्यु दिनांक 3 अगस्त, 1978 को हुई थी। दूसरे प्रत्यर्थी मदन मोहन शर्मा के बेटे सुदर्शन लाल के संबंध में, प्रेम प्रकाश

शर्मा ने दावा किया कि लाल ने उनके पक्ष में एक वसीयत छोड़ी थी, और इस तरह की वसीयत के अनुसार, लाल को संपत्ति में जो भी हिस्सा मिला था, वह उनका था। इसके लिए उन्होंने प्रोबेट मामला सं. 34/1988 का अवलंब लिया, जिसे उन्होंने लाल की वसीयत के संबंध में वर्तमान वाद की शुरुआत से पूर्व दायर किया था। हालाँकि प्रोबेट मामले का निर्णय दिनांक 19 अगस्त, 2005 के आदेश द्वारा प्रेम प्रकाश शर्मा के पक्ष में हुआ था (जिसके विरूद्ध स्वर्ण लता द्वारा नि.प्र.अ. (मू.प.) 103/2005 के रूप में दायर की गई अपील खारिज कर दी गई थी), विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 25 अप्रैल, 2008 के आदेश द्वारा उन्हें (प्रेम प्रकाश शर्मा) वाद में पक्षकार बनने की अनुमति नहीं दी। हालाँकि, प्रेम प्रकाश शर्मा के वरिष्ठ अधिवक्ता की बात भी एकल न्यायाधीश द्वारा सुनी गयी थी।

3. वादी का मामला यह था कि विभाजन से पूर्व, स्वर्गीय बख्शी राम एवं उनका परिवार पंजाब के एक हिस्से में बसे थे जो अब पाकिस्तान में है। उस समय, परिवार एक एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) था और *कर्ता* के रूप में बख्शी राम उस समय विभिन्न व्यवसाय (ठेकेदार के रूप में, तथा एक पेट्रोल पंप) चला रहे थे। दावा किया जाता है कि ये व्यवसाय *"बख्शी राम एंड संस"* के नाम के तहत चलाए जा रहे थे। यह आरोप लगाया गया है कि विभाजन के बाद, बख्शी राम अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से भारत चले आये, तथा अपने व्यवसायों से संबंधित विभिन्न परिसंपत्तियों और संपत्तियों के

संबंध में पुनर्वास मंत्रालय (भारत में) के साथ अपने दावे प्रस्तुत किए तथा साथ ही पाकिस्तान में उनके द्वारा छोड़े गए घरों और अन्य संपत्ति के बारे में भी बताया। आवेदक का नाम *"बख्शी राम एंड संस"* था, *कर्ता* के रूप में बख्शी राम के माध्यम से तथा उल्लिखित पता 16/229, जोशी रोड, करोल बाग, नई दिल्ली था। इस प्रकार, वादी ने आग्रह किया कि दावा स्वर्गीय बख्शी राम द्वारा *कर्ता* के रूप में एक एचयूएफ की ओर से किया गया था।

4. पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्तियों के संबंध में, वादी ने दावा किया कि बख्शी राम ने वर्ष 1930 में किसी समय *"बख्शी राम एंड संस"* फर्म के नाम पर एक फैक्ट्री साइट खरीदी थी। इसके अलावा, वादी कहते हैं कि वह चावल के आटे की मिल के एकमात्र मालिक थे। वादी यह भी दावा करते हैं कि बख्शी राम के पास बर्मा शेल कंपनी का एक पेट्रोल पंप था, जिसे वह शेखपुरा (जो अब पाकिस्तान में है) में चला रहे थे। अंत में, वादी कहते हैं कि बख्शी राम ने कई व्यावसायिक संपत्तियों के साथ-साथ कई आवासीय संपत्तियों का अधिग्रहण/निर्माण किया था *"चाहे वह उनके व्यक्तिगत नाम पर हो या बख्शी राम एंड संस, एक संयुक्त हिंदू परिवार फर्म के नाम पर हो..."*

5. वाद में आरोप लगाया गया है कि विभाजन के बाद बख्शी राम को पाकिस्तान में पीछे रह गई संपत्ति के बदले में विभिन्न संपत्तियां आवंटित की गईं। सबसे पहले, बर्मा शेल कंपनी ने दिल्ली के महरौली तहसील के बदरपुर में एक पेट्रोल पंप मेसर्स बख्शी राम एंड संस को आवंटित किया, जो एक एचयूएफ

फर्म है, जिसके *कर्ता* बख्शी राम थे। इसके अलावा, वादी ने आरोप लगाया है कि बख्शी राम को कुछ मुआवजा राशि भी दी गई थी, जिसका प्रयोग उन्होंने दिल्ली में विभिन्न व्यवसायों को चलाने और संबंधित संपत्तियों के सुधार के संबंध में किया। ये थे बदरपुर, तहसील महरौली, दिल्ली में प्लॉट सं. 43 (950/- रुपये के प्रतिफल के लिए), दिल्ली के आजादपुर गांव में एक 'कुट्टी मशीन', जो कि निष्क्रांत संपत्ति के संरक्षक की थी (किराए के आधार पर), इसके अलावा, वादीगण आरोप लगाते हैं कि बख्शी राम को उनके निर्धारित दावों के विरुद्ध मुआवजे के रूप में जो राशि मिलनी थी, उसके विपरीत, बख्शी राम ने एक संपत्ति - हाउस नंबर XVI/318-323, जोशी रोड, करोल बाग, नई दिल्ली को उक्त संपत्ति की कीमत के प्रति मुआवजे की राशि का एक हिस्सा समायोजित करके अधिग्रहित किया था। महत्वपूर्ण रूप से, वादीगण दावा करते हैं कि बख्शी राम एंड संस की एचयूएफ फर्म के नाम पर व्यवसाय आदि चलाए जा रहे थे, जैसा कि पहले पाकिस्तान में किया जा रहा था, जब तक कि बख्शी राम की मृत्यु दिनांक 10 फरवरी, 1960 को नहीं हो गई। यह दावा किया जाता है कि सुदर्शन लाल ने वर्ष 1987 में अपनी मृत्यु तक कर्ता के रूप में काम किया।

6. वादीगण का दावा है कि इन विभिन्न संपत्तियों की खरीद के पश्चात् (अर्थात् पाकिस्तान से पलायन के बाद), पारिवारिक व्यवसाय (अर्थात् हिंदू

अविभाजित परिवार जैसा कि तब अस्तित्व में था) धीरे-धीरे समृद्ध हुआ, एवं परिवार ने अर्जित धन से कई अन्य संपत्तियां अर्जित कीं। ये थीं:

(क) दिल्ली के महरौली तहसील के तुगलकाबाद में खसरा सं. 2609/727-728 वाला प्लॉट, जिसका माप 5 बीघा, 1 बिस्वा है, परिवार द्वारा खरीदा गया था, एवं इसका उपयोग पेट्रोल पंप चलाने के लिए किया जा रहा है।

> *"जहां तक वादीगण को पता है, यह जमीन मेसर्स बख्शी राम एंड संस द्वारा प्राप्त की गई है, जो एक संयुक्त हिंदू परिवार फर्म है और उक्त भूखंड पर चलाया जा रहा पेट्रोल पंप भी मेसर्स बख्शी राम एंड संस का है।"*

(ख) एक प्लॉट, सं. बी-43, फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली, जो डीडीए द्वारा परिवार की जमीन का एक हिस्सा अधिग्रहित करने के बदले में आवंटित किया गया था। इस प्रकार, वादी आरोप लगाते हैं कि *"यह प्लॉट संयुक्त हिंदू परिवार की भूमि के अधिग्रहण के बदले में डीडीए द्वारा आवंटित किया गया था ..."* (ग) खसरा सं. 32/28/1 एवं 32/28/2 का एक प्लॉट, जिसका माप 2 बीघा, 5 बिस्वा है एवं साथ ही एक प्लॉट सं. 32/28/3 को संयुक्त हिंदू परिवार ने मेसर्स बख्शी राम एंड संस के नाम पर गांव बदरपुर, तहसील महरौली, जिला दिल्ली में अधिग्रहित किया था। वादी का यह भी आरोप है कि यह प्लॉट भी

"मेसर्स बख्शी राम एंड संस, संयुक्त हिंदू परिवार की फर्म का है।" (घ) खसरा संख्या 231 पर स्थित 2 बीघा, 13 बिस्वा का एक प्लॉट, जो गांव ताजपॉल, तहसील महरौली, जिला दिल्ली में है, *"मेसर्स बख्शी राम एंड संस के नाम पर है और इस प्रकार यह भी एक संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति थी",* वादी के कथनों में। (ङ) खसरा संख्या 36/28/2 और 36/29/2 पर स्थित 15 बिस्वा का एक प्लॉट, जिसके बारे में वादी का आरोप है कि *"इसे भी परिवार ने गांव बदरपुर, तहसील महरौली, दिल्ली में संयुक्त हिंदू परिवार के फंड से खरीदा था।"* हालांकि, वादीगण ने आगे कहा कि प्रेम और स्नेह के कारण यह प्लॉट श्रीमती चनन देवी, बख्शी राम की विधवा, अर्थात् आज न्यायालय के समक्ष पक्षकारों की मां के नाम पर खरीदा गया था। (च) आवासीय मकान II-K/44, लाजपत नगर, नई दिल्ली, पुनः, वादीगण का दावा है, *"संयुक्त हिंदू परिवार निधि से अधिग्रहित किया गया था।"*

7. इसके अलावा, वादीगण ने दावा किया कि पारिवारिक व्यवसाय और आय (अर्थात् उपरोक्त संपत्तियों से किराये की आय, और व्यवसाय चलाने से होने वाली आय) के अलावा, वादी के भाई, अर्थात् पहले दो प्रत्यर्थी, *"कोई अन्य व्यवसाय नहीं करते थे और न ही उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत था।"* बख्शी राम की मृत्यु के पश्चात्, वादीगण दावा करते हैं कि सुदर्शन लाल ने कई व्यवसाय किए, कई बैंक खाते, सावधि जमा व विभिन्न कंपनियों के हिस्सा

रखे, जो सभी, हालांकि सुदर्शन लाल के नाम पर थे, वास्तव में एचयूएफ के थे। हालांकि, वादीगण ने निम्नलिखित कहा:

> *"10.....इस समय वादीगण स्वर्गीय सुदर्शन लाल के नाम पर मौजूद विभिन्न बैंक खातों/सावधि जमाओं आदि के संपूर्ण विवरण से अवगत नहीं हैं, साथ ही संयुक्त हिंदू परिवार फर्म मेसर्स बक्शी राम एंड संस एवं वाद में बताई गई अन्य फर्मों के नाम पर विभिन्न बैंक खातों और सावधि जमाओं आदि के बारे में भी नहीं जानते हैं। इस संबंध में विवरण प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 के विशेष ज्ञान में हैं। वादीगण उनकी ओर से विवरण का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही वादीगण को यह ज्ञात होगा या प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 द्वारा अन्यथा प्रकट किया जाएगा, वे इसे प्रस्तुत करेंगे....."*

8. वाद में आरोपित इन तथ्यों के आधार पर, वादी ने दावा किया कि बख्शी राम और श्रीमती चनन देवी के वर्ग I वारिस के रूप में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (एतद्पश्चात् "एचएसए") के तहत, वे एचयूएफ संपत्तियों और अपनी मां द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों में एक-सातवें बराबर हिस्से के हकदार थे (अर्थात् पांच बहनों व दो भाइयों के बीच साझा करना, सुदर्शन लाल को छोड़कर, जिनकी मृत्यु कुंवारे ही हुई थी)। इसके अलावा, सुदर्शन लाल की संपत्तियों के संबंध में, यह तर्क दिया गया कि वादी तथा प्रतिवादी, एचएसए के तहत उनके वर्ग II के विधिक वारिस हैं और इस प्रकार वे उनके नाम पर मौजूद सभी संपत्तियों में 1/7वें हिस्से के हकदार हैं। वैकल्पिक अभिवचन के

रूप में, यह तर्क दिया गया कि सुदर्शन लाल की संपत्तियां वास्तव में एचयूएफ की संपत्तियां थीं

9. इसके अलावा, वादी का दावा है कि बख्शी राम या श्रीमती चनन देवी, या यहां तक कि सुदर्शन लाल की मृत्यु तक, पारिवारिक संपत्तियों का कोई विभाजन नहीं हुआ था एवं संपत्तियां संयुक्त रूप से बनी रहीं तथा सभी पक्षकारों का उसमें अपना-अपना अविभाजित हिस्सा रहा।

10. पहले दो प्रत्यर्थीगण (अर्थात् दोनों भाइयों) ने एक साझा लिखित बयान दाखिल किया; तीसरे एवं चौथे प्रत्यर्थीगण पेश नहीं हुए और उन्हें *एकपक्षीय* निर्णय सुनाया गया। दोनों भाइयों ने अभिवचन दिया कि: (1) पहले दो वादीगण, तथा वर्तमान अपील में गैर-प्रतिवादी अपीलार्थी, वर्ष 1944 एवं वर्ष 1951 में, अर्थात् 1956 में एचएसए के समक्ष विवाहित थे, और इस तरह वे एचयूएफ के सदस्य नहीं थे; (2) जब दिनांक 10 फरवरी, 1960 को बख्शी राम की मृत्यु हुई, उसके बाद दिनांक 21 फरवरी, 1960 को एचयूएफ के सभी सदस्य क्रिया समारोह में एकत्र हुए और एचयूएफ को अलग करने और संपत्ति को बांटने पर सहमत हुये। इस संबंध में उन्होंने अलग होने के अपने उद्देश्य की स्पष्ट और निश्चित घोषणा की। तदनुसार, यह तर्क दिया गया कि वादी, ऐसे समझौते के पक्षकार होने के नाते, विभाजन की वैधता पर सवाल उठाने से रोक दिये गये (3) यह वाद अनुच्छेद 113, सीमा अधिनियम, 1963 के तहत समय बीत चुका था; (4) मकान सं. XVI/318-323, जोशी रोड, करोल बाग, नई

दिल्ली पर वादी के दावे के संबंध में, भाइयों ने दावा किया कि परिवार के सदस्यों (वादी सहित) के बीच हुए समझौते के अनुसार, वादी ने सुदर्शन लाल के पक्ष में पंजीकृत दस्तावेज के तहत प्लॉट पर अपना अधिकार/दावा त्याग दिया था; (5) पाकिस्तान में पेट्रोल पंप एचयूएफ का नहीं बल्कि बख्शी राम, सुदर्शन लाल और कुलभूषण लाल की साझेदारी फर्म का था; (6) इसी तरह, वर्ष 1947 में बदरपुर में मेसर्स बर्मा शेल द्वारा दिनांक 01.12.1948 के एक समझौते द्वारा आवंटित पेट्रोल पंप साझेदारी फर्म (न कि एचयूएफ) को था; (7) *कुट्टी* मशीन और *रेहरा* स्टैंड के अस्तित्व से इनकार किया गया; (8) श्री बख्शी राम के निधन के समय, संयुक्त परिवार की संपत्तियों में केवल जोशी रोड, करोल बाग में उपर्युक्त घर शामिल था; बदरपुर गांव में खसरा सं. 36/28/2 और 36/29/2 की प्लॉट सं. 43, एवं बदरपुर गांव में खसरा संख्या 32/28/1 और 32/28/2 वाली जमीन; (9) करोल बाग का घर बख्शी राम और उनके तीन बेटों (साझेदारी फर्म के रूप में) को उनके नाम पर देय मुआवजा राशि के विरुद्ध अधिग्रहित किया गया था, तथा उनकी मृत्यु के पश्चात्, वर्तमान मामले के सभी पक्षकारों ने एक पंजीकृत विलेख द्वारा सुदर्शन लाल के पक्ष में संपत्ति में अपने अधिकारों को छोड़ दिया, तथा इसके अलावा, कि संपत्ति इस प्रकार एमसीडी और डीडीए के रिकॉर्ड में सुदर्शन लाल के पक्ष में नामांतरण की गई थी; (9) बदरपुर में प्लॉट सं. 43 (खसरा सं. 36/28/2 एवं 36/29/2) को बख्शी राम ने दावों के विरूद्ध पुनर्वास मंत्रालय से अधिग्रहित किया था। उनके निधन और

एचयूएफ के विघटन पर उक्त प्लॉट पक्षकारों की मां श्रीमती चनन देवी के पास आ गया। उन्होंने वर्ष 1960 के आसपास प्लॉट सं. 43 के संबंध में दिल्ली के वरिष्ठ उप-न्यायाधीश की न्यायालय में अपने तीन बेटों के बयान पर मालिक और भूमिदार के रूप में अपने अधिकारों की घोषणा की मांग करते हुए एक वाद दायर किया था। उक्त भूमि का स्वामी एवं भूमिदार घोषित करते हुए घोषणा-पत्र जारी किया गया; राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि का नामांतरण भी उसके नाम पर किया गया; (10) खसरा सं. 32/28/1 एवं 32/28/2 में स्थित भूखण्ड पारिवारिक समझौते के अनुसार बख्शी राम के तीन पुत्रों में निहित है तथा उनके नाम पर भी नामांतरण किया गया; (11) एचयूएफ के विघटन पर, तीनों भाइयों ने प्रत्येक बहन को 10,000/- रुपए देने पर सहमति जताई थी और जो भुगतान किया गया था; (12) सितंबर, 1958 से सभी भाई अलग-अलग रह रहे थे; इस बात से इनकार किया गया कि कोई भी व्यवसाय एचयूएफ का था; (13) तुगलकाबाद में 5 बीघा और 1 बिस्वा भूमि के संबंध में यह कहा गया कि इसे सुदर्शन लाल ने अपने निजी कोष से और दिनांक 11 जून, 1960 को पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा अधिग्रहित किया था और बख्शी राम एंड संस का उक्त भूमि से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने पेट्रोल पंप के लिए बर्मा शेल को भूखंड का एक हिस्सा पट्टे पर दिया था और बीई-एआर सेल्स (ऑटो ग्रिट) के नाम में पेट्रोल पंप वर्ष 1961 से सुदर्शन लाल और प्रत्यर्थी सं. 1 के बीच साझेदारी में काम कर रहा था; बाद में प्रेम प्रकाश शर्मा

उक्त फर्म में शामिल हो गए। इस बात से इनकार किया गया कि पेट्रोल पंप (ऑटो ग्रिट) बख्शी राम एंड संस का था; यह भी कहा गया कि इसके नीचे की जमीन अधिग्रहित की गई थी और सुदर्शन लाल ने इस अधिग्रहण को चुनौती देते हुए इस न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी; रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान सुदर्शन लाल की मृत्यु हो गई और उनके स्थान पर प्रेम प्रकाश शर्मा को प्रतिस्थापित किया गया; (14) सुदर्शन लाल ने वर्ष 1968 में अपने स्वयं के धन से तेहखंड गांव में 2 बीघा और 10 बिस्वा जमीन अधिग्रहित की थी और इसका बिक्री विलेख केवल उनके नाम पर था और यह उनकी एकमात्र संपत्ति थी; इसे अधिग्रहित किया गया था और इसके बदले में सुदर्शन लाल को प्लॉट सं. बी-43 फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली आवंटित किया गया था; (15) बदरपुर गांव में खसरा सं. 32/28/1 और 32/28/2 में जमीन के संबंध में यह कहा गया कि हालांकि यह बख्शी राम की थी, लेकिन उनकी मृत्यु पर दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के प्रावधानों के तहत जमीनों को उनके तीन बेटों के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया था; उक्त जमीनें अधिग्रहित की गई थीं; अधिग्रहण को बख्शी राम के तीन बेटों द्वारा भी चुनौती दी गई थी; (16) वादी द्वारा वर्णित खसरा सं. 32/28/3 वाली कोई जमीन नहीं थी; (17) खसरा सं. 231, गांव ताजपौल, तहसील महरौली में 2 बीघा 16 बिस्वा जमीन सुदर्शन लाल की एकमात्र संपत्ति थी जिसे वर्ष 1957 में अधिग्रहित किया गया था और वर्ष 1968 में सुदर्शन लाल ने बख्शी राम एंड संस के नाम में एचयूएफ

का गठन किया था और वह इसके कर्ता थे। (18) लाजपत नगर स्थित घर वर्ष 1958 से दूसरे प्रतिवादी की किरायेदारी में था; यह दावा किया गया था कि उक्त घर प्रेम प्रकाश शर्मा द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 1989 की बिक्री विलेख द्वारा खरीदा गया था; घर तब से बेचा जा चुका है; (18) बीई-एआर सेल्स सुदर्शन लाल और प्रथम प्रतिवादी की साझेदारी थी और यह ऑटो रेस्ट, ऑटो रिंक और ऑटो ग्रिट के नाम में कारोबार कर रही थी; बाद में प्रेम प्रकाश शर्मा भी उक्त फर्म में शामिल हो गये। पेट्रोल पंप ऑटो यार्ड अप्रैल, 1966 से दूसरे प्रतिवादी का एकमात्र मालिकाना हक था और फरवरी 1987 से इसे प्रतिवादी सं. 2 और उसकी पत्नी की साझेदारी फर्म में बदल दिया गया था। शर्मा एंड कंपनी के नाम में किसी भी फर्म के अस्तित्व से इनकार किया गया।

11. दिनांक 8 सितम्बर, 1994 को तथा उसके बाद दिनांक 11 दिसम्बर, 2001 को न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तय किये गये:

> *"1. क्या वादी 1 व 2 के पास क्रमशः वर्ष 1994 (1944) और 1951 में विवाह होने के बावजूद संयुक्त परिवार की संपत्ति में कोई अधिकार और हित है? ओपीपी*
>
> *2. क्या वादी को संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन के लिए वाद दायर करने का अधिकार है?*
>
> *3. क्या यह वाद सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 113 के तहत समय से वर्जित है? ओपीडी1डी2*

4. क्या दिनांक 21.2.60 को बख्शी राम एंड संस के संयुक्त हिंदू परिवार की स्थिति का विच्छेद हुआ था? ओपीडी1डी2

5. दिनांक 10.2.60 को श्री बख्शी राम की मृत्यु के समय बख्शी राम एंड संस के पास क्या संपत्तियां थीं? ओपीपी

6. बख्शी राम की मृत्यु के समय संयुक्त परिवार की संपत्ति में उनका हिस्सा कितना था? ओपीपी

7. संयुक्त परिवार की संपत्ति में स्वर्गीय बख्शी राम के हिस्से का प्रत्येक वादी कितना हिस्सा पाने का हकदार है? ओपीपी

8. क्या वादीगण, जिन्होंने प्रतिवादी सं. 4 के साथ मिलकर मकान संख्या XVI/318 और 323, जोशी रोड, करोल बाग, नई दिल्ली पर अपने अधिकार/दावे को पंजीकृत दस्तावेजों के तहत अपने भाई सुदर्शन लाल के पक्ष में त्याग दिया था, अब भी उस मकान पर दावा कर सकते हैं? ओपीपी

9. क्या वादीगण खसरा सं. 32/28/1 और 32/28/2 की भूमि में किसी हिस्से का दावा कर सकते हैं, जिसका दाखिल खारिज दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के तहत बख्शी राम की मृत्यु के बाद उनके तीन बेटों के नाम पर कर दिया गया था? ओपीपी

10. क्या वादीगण दिल्ली के बदरपुर गांव में स्थित खसरा संख्या 36/28/2 और 36/29/2 वाले प्लॉट संख्या 43 में किसी हिस्से का दावा कर सकते हैं, जिसका नाम दिनांक 18.2.63 को उनकी मां चानन देवी के नाम पर स्थानांतरण किया गया था, जब उन्हें भूमिदार घोषित किया गया था? ओपीपी

11. क्या वादीगण किसी अन्य सम्पत्ति में हिस्सेदारी का दावा कर सकते हैं जिसे प्रतिवादी 1 व 2 ने अपने पिता बख्शी राम की मृत्यु के बाद अपने स्वयं के धन से खरीदा या अर्जित किया था? ओपीपी

11क. क्या वाद का मूल्यांकन न्यायालय शुल्क और अधिकारिता के लिए उचित रूप से किया गया है? यदि नहीं, तो इसका प्रभाव क्या होगा?

12. अनुतोष"।

12. इस समय यह उपयोगी होगा कि उन विभिन्न संपत्तियों को सारणीबद्ध किया जाए जिनका विभाजन अपीलार्थी द्वारा किया जाना है।

संपत्ति	**विवरण**
पेट्रोल पंप	बदरपुर, तहसील महरौली
एक कुट्टी मशीन	आजादपुर
रेहरा स्टैंड	फरशखाना, जी. बी. रोड, दिल्ली
प्लॉट की माप 5 बीघे, 1 बिस्वा	महरौली
प्लॉट सं. बी-43	फ्रैंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली
खसरा संख्या 36/28/1-3 वाले प्लॉट	गाँव बदरपुर, तहसील महरौली
15 बीघा का प्लॉट, खसरा सं. 36/28/2 और 29/2	गाँव बदरपुर, तहसील महरौली
मकान सं. II-के/44	लाजपत नगर, नई दिल्ली

निम्नलिखित के नाम पर व्यवसाय क) तुगलकाबाद, तहसील महरौली में ऑटो ग्रिट; ख) बदरपुर, तहसील महरौली में ऑटो रिंक; ग) बदरपुर में ऑटो रेस्ट; घ) मथुरा रोड पर ऑटो यार्ड; ङ) बदरपुर में बीई एआर सेल्स; च) बदरपुर में शर्मा एंड कंपनी के नाम पर व्यवसाय।	
विभिन्न अन्य बैंक खाते, सावधि जमा और आभूषण, हालांकि इन वस्तुओं का विवरण अपील ज्ञापन की शिकायत में नहीं दिया गया है।	
मकान सं. 16/229	जोशी रोड, करोल बाग, नई दिल्ली
भूखंड संख्या 231	गाँव तेजपॉल, तहसील महरौली, दिल्ली

13. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिलेख पर मौजूद सबूतों पर विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में वर्ष 2005 में किया गया संशोधन (जिसने एचयूएफ की महिला सदस्यों को भी सहदायिक सदस्य बनाया) लागू नहीं होगा क्योंकि *मुकेश बनाम भरत सिंह,* 149 (2008) डीएलटी 114 में दिए गए कथन के मद्देनजर यह संशोधन पूर्वव्यापी नहीं था। परिणामस्वरूप विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि वाद संशोधन से पहले शुरू किया गया था और इसके अलावा,

चूंकि बख्शी राम की मृत्यु संशोधन से 35 साल पहले हुई थी, अतः वादी - एचयूएफ की महिला सदस्य होने के नाते - सह-दायिक के रूप में कोई अधिकार नहीं रखते है। इसके अलावा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि बख्शी राम की मृत्यु की तिथि को एक विभाजन हुआ था हालांकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि वादी, एचएसए की धारा 8 के तहत स्वर्गीय बख्शी राम के सहदायिक संपत्ति में हिस्से के वर्ग I वारिस के रूप में उत्तराधिकार के माध्यम से हिस्सेदारी के हकदार होंगे। इस प्रकार, इस बाद के आधार पर, यह अभिनिर्धारित किया गया कि वादी को वाद करने का अधिकार था, लेकिन सहदायिक के रूप में नहीं। सीमा के सवाल पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पहले दो प्रतिवादीगण के अभिवचनों को गलत माना कि मुकदमा समय-बाधित था क्योंकि विभाजन वर्ष 1960 में बख्शी राम के निधन पर हुआ था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह विभाजन साबित नहीं हुआ था। इसके विपरीत, पहले और दूसरे प्रतिवादीगण ने दिनांक 1 अप्रैल, 1968 के साझेदारी विलेख और रि.या.(सि.) सं. 1921/1986 में एचयूएफ के अस्तित्व को स्वीकार किया। एचयूएफ द्वारा कथित रूप से चलाए जा रहे विभिन्न व्यवसायों के संबंध में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि प्र.अभि.-20 के रूप में प्रस्तुत भागीदारी विलेख के माध्यम से यह साबित हुआ कि उन्हें मुकदमा शुरू होने से लगभग 22 वर्ष पहले दिनांक 01.04.1968 से एचयूएफ से बाहर कर दिया गया था, और परिवार के पुरुष सदस्यों के बीच साझेदारी में चलाया

गया था। इन व्यवसायों के खातों के बंटवारे और प्रतिपादन के दावे के संबंध में समय-बाधित माना गया।

14. इस प्रश्न पर कि बख्शी राम की मृत्यु के समय कौन सी संपत्तियां एचयूएफ का हिस्सा थीं, अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल, 1968 के साझेदारी विलेख के रूप में पहले एवं दूसरे प्रतिवादीगण के प्रवेश के आधार पर, नामित एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि निम्नलिखित संपत्तियां संयुक्त रूप से आयोजित की गई थीं: क) जोशी रोड, करोल बाग में घर, ख) प्लॉट सं. 43 जिसमें खसरा सं. 36/28/2 व 36/29/2 गाँव बदरपुर, दिल्ली में, ग) गाँव बदरपुर, दिल्ली में खसरा सं. 32/28/1 व 32/28/2 वाली भूमि का प्लॉट, घ) भूमि सं. 232, गाँव तेजपाल, तहसील महरौली, दिल्ली का प्लॉट और अंत में, ङ) तुगलकाबाद में भूमि का एक प्लॉट। इन संपत्तियों में से, बख्शी राम का पांचवां हिस्सा (पूरा हिस्सा परिवार के पांच सदस्यों के बीच विभाजित किया जा रहा है जो सहदायिक में भाग लेंगे, अर्थात् वह, उनकी पत्नी और तीन बेटे) आठ बच्चों और स्वर्गीय बख्शी राम की विधवा को दिया जाएगा। इस प्रकार, स्वतंत्र एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्येक वादी स्वर्गीय बख्शी राम के 1/5वें हिस्से के 1/8वें हिस्से का हकदार होगा। हालांकि, जोशी रोड, करोल बाग में घर के संबंध में, एकल न्यायाधीश ने कहा कि वादी ने एक पंजीकृत त्याग विलेख (जिसे वादी द्वारा स्वीकार किया गया था) के माध्यम से उस संपत्ति पर कोई भी दावा सुदर्शन लाल को सौंप दिया था। इसके अलावा, दिल्ली

के गाँव बदरपुर में भूखंड सं. 43 जिसमें खसरा सं. 36/28/2 व 36/29/2 शामिल है, के संबंध में एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि यह स्वीकार किया गया था और स्थापित किया गया था कि संपत्ति का स्थान माता, श्रीमती के नाम पर परिवर्तित किया गया था। जमीनदार के रूप में चनन देवी और इस प्रकार, दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 51 के प्रावधान इस तथ्य के बावजूद लागू होंगे कि भूमि का शहरीकरण किया गया होगा। तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 51 के तहत, परिवार के केवल पुरुष सदस्य ही भूमि के हकदार होंगे, एवं वादी को किसी भी हिस्से से बाहर रखा जाएगा। इस प्रकार, अंतत, न्यायसम्मत एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि केवल वे संपत्तियां जिनमें वादी का हिस्सा हो सकता है, वे हैं जिन्हें दिनांक 1 अप्रैल, 1968 के साझेदारी विलेख में स्वीकार किया गया था, जिनके ऊपर दावा त्याग दिया गया था, या जिन्हें दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम द्वारा विनियमित किया गया था। इस पर, नामित एकल न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि तीन संपत्तियां बची हैं जिनमें वादी का हिस्सा था, अर्थात्) गाँव बदरपुर, दिल्ली में खसरा संख्या 32/28/1 व 32/28/2 वाली भूमि का भूखंड, ख) भूमि संख्या 211 वाला भूखंड, गाँव तेजपॉल, तहसील महरौली, दिल्ली और अंतत, ग) तुगलकाबाद में भूमि का एक भूखंड। हालांकि, नामित एकल न्यायाधीश ने कहा कि भूमि सुधार अधिनियम की धारा 185 अधिनियम द्वारा शासित संपत्तियों के संबंध में सिविल न्यायालयों

की अधिकारिता को प्रतिबंधित करती है, भले ही भूमि एचयूएफ या किसी व्यक्तिगत परिवार के सदस्य के पक्ष में परिवर्तित की गई हो। तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 185 के तहत प्रतिबंध को देखते हुए इस वाद में तीन में से किसी भी संपत्ति का विभाजन नहीं किया जा सकता है।

15. विद्वान एकल न्यायाधीश के इस आदेश एवं निर्णय को गलत बताते हुए तीसरे वादी के वकील ने आग्रह किया कि यह निष्कर्ष कि विचाराधीन संपत्तियां सहदायिक संपत्तियां हैं, स्व-अर्जित संपत्तियां नहीं हैं और एचएसए की धारा 8 द्वारा विनियमित हैं, त्रुटिपूर्ण है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह मानने का कोई आधार नहीं है कि संपत्तियां सहदायिक हैं, क्योंकि उनके पैतृक प्रकृति का कोई सबूत अभिलेख में नहीं था। इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता ने सुदर्शन लाल के पक्ष में त्याग विलेख की वैधता पर सवाल उठाया और आग्रह किया कि ऐसा कोई हवाला नहीं है कि निष्पादक ने सत्यापन करने वाले साक्षी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और सत्यापन करने वाले साक्षी ने निष्पादक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए, जो कि विधि के तहत एक आवश्यकता है। इसके बाद, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उस हिस्से को स्वीकार करने के बावजूद, निर्णय में कोई तर्क दिए बिना मां चनन देवी के 1/5 वें हिस्से का विभाजन नहीं किया। अंतत, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मानते हुए त्रुटि की कि वर्ष 2005 में

संशोधित धारा 6, एचएसए लागू नहीं थी, क्योंकि वाद दायर होने से पहले या संशोधन की तिथि तक कोई विभाजन नहीं हुआ था। अधिवक्ता ने धारा 6(1) के प्रावधान के साथ-साथ धारा 6(5) पर भरोसा किया और तर्क दिया कि एक बार जब विधानमंडल ने विशेष रूप से यह प्रावधान किया था कि किस श्रेणी के मामलों को संशोधन से बाहर रखा गया है, तो एकल न्यायाधीश द्वारा यह मानने का कोई सवाल ही नहीं था कि अपीलार्थी और दूसरी बेटी का संपत्ति में हिस्सा पिता के 1/5वें हिस्से तक सीमित था, या तो काल्पनिक विभाजन के आधार पर, या इस समझ के आधार पर कि वाद दायर करने पर विभाजन हुआ था। दूसरे शब्दों में, विभाजन की किस श्रेणी को स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के बाद समाप्त और अंतिम माना जाता है, न्यायालय बेटियों के हिस्से से इनकार नहीं कर सकता था, जो वर्ष 2005 के संशोधन के अधिनियमन और लागू होने पर उन्हें मिला था। तदनुसार, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि संशोधन के लागू होने की तिथि तक एचयूएफ अक्षुण्ण था - चूंकि कोई विभाजन नहीं हुआ था, अंतिम डिक्री से उत्पन्न विभाजन तो दूर की बात थी, विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि बख्शी राम के निधन पर एक काल्पनिक विभाजन हुआ था और इससे पहले दो प्रतिवादीगण के अधिकार स्पष्ट हो गए थे, एचएसए के विपरीत था।

16. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि आक्षेपित निर्णय अनुरक्षणीय नहीं है क्योंकि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 507(क) के

तहत जारी अधिसूचनाओं के कारण कई संपत्तियों का शहरीकरण हो गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि इस विकास के कारण, दिल्ली सुधार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अधिवक्ता ने *श्रीमती इंदु खोराना बनाम ग्राम सभा और अन्य, एमएएनयू/डीइ/0969/2010* में इस न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ के निर्णय पर भरोसा किया।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

17. इस मामले में न्यायालय के विचारार्थ चार प्रश्न उठते हैं: पहला, क्या विचाराधीन विभिन्न संपत्तियां प्रारंभ में सहदायिक संपत्तियां थीं, या बख्शी राम की स्व-अर्जित संपत्तियां थीं; दूसरा, क्या विचाराधीन संपत्तियों को बख्शी राम की मृत्यु की तिथि को विभाजित माना जाना चाहिए, या क्या उन्हें बाद की तिथि को विभाजित किया जाना है; तीसरा, क्या इस मामले में धारा 6 में वर्ष 2005 का संशोधन प्रभावी है; परिणामस्वरूप, पक्षकारों के हिस्से क्या हैं; चौथा, क्या कोई संपत्ति दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के तहत उत्तराधिकार नियमों द्वारा शासित है, और इस प्रकार, इस न्यायालय के विषय-वस्तु अधिकारिता से बाहर है।

18. पहले प्रश्न पर, स्वतंत्र एकल न्यायाधीश ने इस निष्कर्ष पर आगे बढ़ते हुए कहा कि संपत्तियां सहदायिक संपत्तियां थीं। वादी का मामला यह है कि बख्शी राम अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से भारत चले गए और उन्होंने पाकिस्तान में अपने द्वारा छोड़ी गई विभिन्न संपत्तियों, घरों और अन्य संपत्तियों

के संबंध में भारत में पुनर्वास मंत्रालय के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत किया। इस आवेदन में, कर्ता के रूप में बख्शी राम द्वारा से आवेदक का नाम *"बख्शी राम एंड संस"* था, और उल्लिखित पता 16/229 जोशी रोड, करोल बाग, नई दिल्ली था। वास्तव में, प्रवास के बाद, वादपत्र में आरोप लगाया गया है कि बख्शी राम को पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्तियों के बदले में विभिन्न संपत्तियां आवंटित की गई थीं, इस प्रकार यह संयुक्त पारिवारिक संपत्ति भी है। वास्तव में, यह निर्विवाद है कि इन विभिन्न संपत्तियों की खरीद (अर्थात् पाकिस्तान से प्रवास के बाद, और सरकार द्वारा भुगतान किए गए मुआवजे) के बाद, पारिवारिक व्यवसाय (अर्थात् हिंदू संयुक्त परिवार जो उस समय मौजूद था) धीरे-धीरे समृद्ध हुआ, और विभिन्न अन्य संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया था। ये थेः (क) तुगलकाबाद, तहसील महरौली, दिल्ली में स्थित खसरा नं. 2609/727-728 वाला एक प्लॉट, जिसका माप 5 बीघा, 1 बिसवा है, परिवार द्वारा प्राप्त किया गया था, तथा इसका उपयोग पेट्रोल पंप चलाने के लिए किया जा रहा है। जहाँ तक वादी को पता है, यह प्लॉट *एक संयुक्त हिंदू परिवार की कंपनी मैसर्स बख्शी राम एंड संस द्वारा प्राप्त किया गया है और उक्त प्लॉट पर चलाया जा रहा पेट्रोल पंप भी मैसर्स बख्शी राम एंड संस का है।"* (ख) एक प्लॉट, सं. बी-43, फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली, जिसे डीडीए द्वारा डीडीए के बदले में पारिवारिक भूमि के एक हिस्से का अधिग्रहण करके आवंटित किया गया था। इस प्रकार, वादी आरोप लगाते हैं कि *"यह प्लॉट संयुक्त हिंदू परिवार की भूमि के अधिग्रहण*

के बदले डीडीए द्वारा आवंटित किया गया था ..." (ग) खसरा सं. 32/28/1 व 32/28/2 का प्लॉट, जिसका माप 2 बीघा, 5 बिस्वा है और साथ ही प्लॉट सं. 32/28/3 को *"संयुक्त हिंदू परिवार द्वारा मेसर्स बख्शी राम एंड संस के नाम पर"* गांव बदरपुर, तहसील महरौली, जिला दिल्ली में अधिग्रहित किया गया था। वादी आरोप लगाते हैं कि यह प्लॉट भी "मेसर्स बख्शी राम एंड संस, संयुक्त हिंदू परिवार की फर्म का है।" (घ) खसरा सं. 231 का प्लॉट, जिसका माप 2 बीघा, 13 बिस्वा है, गांव ताजपुल, तहसील महरौली, जिला दिल्ली में, *"मेसर्स बख्शी राम एंड संस के नाम पर और इस प्रकार यह भी एक संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति थी",* वादी के कथनों में (ङ) खसरा संख्या 36/28/2 व 36/29/2 वाला 15 बिस्वा का प्लॉट, जिसके बारे में वादी का आरोप है कि, *"इसे भी परिवार ने दिल्ली के तहसील महरौली के बदरपुर गांव में संयुक्त हिंदू परिवार के फंड से खरीदा था।"* (च) आवासीय घर II-K/44, लाजपत नगर, नई दिल्ली, पुनः, वादी का दावा है, *"संयुक्त हिंदू परिवार के फंड से खरीदा गया था।"* वादपत्र में इन कथनों को देखते हुए, न्यायालय को विद्वान एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है कि ये संपत्तियां बख्शी राम की स्व-अर्जित संपत्तियां नहीं थीं, बल्कि उस समय संयुक्त परिवार की संपत्तियां थीं।

19. दूसरे प्रश्न पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि *"बख्शी राम के निधन के समय उक्त एचयूएफ का विभाजन माना जाता है..."*

और इस प्रकार, हिस्साो ं को उसी समय विभाजित किया जाता है। एचएसए के तहत, सहदायिक के सदस्य की मृत्यु पर, न तो सहदायिक और न ही एचयूएफ टूटता है। वर्ष 2005 के संशोधन से पहले, सहदायिक संपत्ति उत्तरजीविता द्वारा शेष सहदायिकों में निहित रहती थी, अर्थात् शेष जीवित सहदायिक (अर्थात् परिवार के पुरुष सदस्य) संयुक्त रूप से संपत्ति रखते थे। जैसा कि मेनेस् हिंदू लॉ एंड यूसेज अभिलिखित हैं:

> *"पुरुष सदस्यों के अधिकार, जो जन्म से उत्पन्न होते हैं, विभाजन पर ही सुनिश्चित होते हैं; क्योंकि, परिवार का कोई भी व्यक्तिगत सदस्य, जब तक वह अविभाजित रहता है, संयुक्त अविभाजित संपत्ति के बारे में यह नहीं कह सकता कि उसका कोई निश्चित हिस्सा है। अविभाजित संपत्ति में सदस्य का हित व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, बल्कि यह एक अस्थिर हित है जो परिवार में जन्म के साथ कम हो सकता है या मृत्यु के साथ बढ़ सकता है।" (पृष्ठ 667, 16वां संस्करण, भारत लॉ हाउस, 2003) (जोर दिया गया)*

20. तदनुसार, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु मात्र से सहदायिक हित का विभाजन नहीं होता, बल्कि शेष सहदायिकों के बीच इसका संशोधन होता है। सहदायिक हित का यह संशोधन, वर्ष 1960 में, जब बख्शी राम की मृत्यु हो गई, एचएसए की असंशोधित धारा 6 द्वारा विनियमित किया गया, जो इस प्रकार है:

"जब इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात किसी हिन्दू पुरुष की मृत्यु हो जाती है, तथा उसकी मृत्यु के समय मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति में उसका हित था, तो संपत्ति में उसका हित सहदायिक के जीवित सदस्यों पर उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित हो जाएगा, तथा यह इस अधिनियम के अनुसार नहीं होगा:

बशर्ते यदि मृतक ने अपने पीछे अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट कोई महिला नातेदार या उस वर्ग में विनिर्दिष्ट कोई पुरुष नातेदार छोड़ा है, जो ऐसी महिला नातेदार के माध्यम से दावा करता है, तो मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति में मृतक का हित इस अधिनियम के अधीन वसीयती या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा, जैसा भी मामला हो, न्यागत होगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा होगा।

स्पष्टीकरण I: इस धारा के प्रयोजनों के लिए, हिंदू मिताक्षरा सहदायिक का हित संपत्ति में वह हिस्सा माना जाएगा जो उसे आवंटित किया गया होता यदि संपत्ति का विभाजन उसकी मृत्यु से तुरंत पहले हुआ होता, भले ही वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं।"

21. अतः, किसी पुरुष रिश्तेदार की मृत्यु के मामले में, जिसमें कोई महिला वर्ग I वारिस नहीं है, किसी विभाजन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, और उत्तरजीविता का नियम बिना किसी बाधा के काम करना था। हालाँकि, जैसा कि इस मामले में हुआ, चूँकि बख्शी राम अपनी पत्नी और पाँच बेटियों को पीछे छोड़कर स्वर्गवासी हो गये, जो सभी वर्ग I वारिस हैं, अतः प्रावधान लागू होगा, और न्यायालय को मृतक बख्शी राम के सहदायिक संपत्ति में हित का पता

लगाने के लिए एक विभाजन करना चाहिए। हालाँकि, यह अभ्यास परिवार के बीच वास्तविक विभाजन में तब्दील नहीं होता है, न ही यह परिवार के शेष पुरुष सदस्यों के बीच सहदायिकता की निरंतरता को प्रभावित करता है। बल्कि, प्रावधान के अनुसार, मृतक का हिस्सा, यदि विभाजन हुआ था, तो उसे एचएसए की धारा 8 के अनुसार अर्थात् उत्तराधिकार के अनुसार विभाजित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, कथित विभाजन का प्रभाव मृतक के हिस्से का पता लगाने तक सीमित है, जिसका दावा उसके वर्ग I के उत्तराधिकारियों द्वारा किया जाता है, बजाय इसके कि यह दावा किया जाए कि संपूर्ण सहदायिक के संबंध में विभाजन होता है, जो कि विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश और निर्णय का तात्पर्य है। जबकि पारंपरिक हिंदू विधि में इस तरह के कथित विभाजन की आवश्यकता नहीं थी, और सहदायिक संपत्ति बनी रहेगी, जैसा कि मेने ने ऊपर बताया है, शेष सहदायिकों के बीच उतार-चढ़ाव होता रहेगा, असंशोधित धारा 6 के प्रावधान के माध्यम से, संपत्ति के विभाजन की इस पद्धति से एक स्पष्ट वैधानिक प्रस्थान है। हालांकि, प्रावधान सीमित है, हालांकि मृतक का हिस्सा सहदायिक से हटा दिया गया है और एचएसए की धारा 14 के माध्यम से महिला रिश्तेदारों में पूर्ण हिस्से के रूप में निहित है, सहदायिक संपत्ति का शेष हिस्सा बरकरार रहता है, संयुक्तता की उसी स्थिति में जैसा कि पहले था और उतार-चढ़ाव वाले ब्याज के समान नियमों के अधीन था। तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि बख्शी राम की मृत्यु के समय एक

समझा हुआ विभाजन था, निस्संदेह सही है, इसका मतलब यह नहीं है कि इस वाद के लिए सहदायिक संपत्ति में हिस्साोंं का निर्णय उस घटना के अनुसार किया जाएगा या हिस्सा क्रिस्टलीकृत हो गए होंगे और अपरिवर्तनीय हो गए होंगे। इसके बजाय, सहदायिक जारी रहा, और हिस्साोंं की सीमा वास्तविक विभाजन के समय तय की जाएगी, या तो विभाजन के पंजीकृत विलेख या इस न्यायालय के डिक्री के माध्यम से, जैसा कि नीचे समझाया गया है।

22. इस न्यायालय के समक्ष तीसरा प्रश्न यह है कि क्या एचएसए की धारा 6 में वर्ष 2005 का संशोधन इस मामले में लागू है। इस चर्चा में प्रवेश करने से पूर्व, इसके प्रासंगिक भाग में संशोधन धारा 6 को उद्धृत करना उपयोगी होगा:

> *"6. **सहदायिक संपत्ति में हित का हस्तांतरण***
>
> *(1) हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से, मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में, सहदायिक की पुत्री,- (क) जन्म से अपने अधिकार में उसी प्रकार सहदायिक होगी जिस प्रकार पुत्र होता है; (ख) सहदायिक संपत्ति में उसके वही अधिकार होंगे जो पुत्र होने पर होते है; (ग) उक्त सहदायिक संपत्ति के संबंध में पुत्र के समान ही दायित्वों के अधीन होगी तथा हिंदू मिताक्षरा सहदायिक के किसी संदर्भ में सहदायिक की पुत्री के संदर्भ को सम्मिलित माना जाएगा:*
>
> *बशर्ते कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात दिनांक 20 दिसंबर, 2004 से पूर्व हुए संपत्ति के विभाजन या वसीयती निपटान सहित*

किसी निपटान या अन्य संक्रामण को प्रभावित या अवैध नहीं करेगी।

(2) कोई संपत्ति, जिस पर कोई हिन्दू स्त्री उपधारा (1) के आधार पर हकदार हो जाती है, उसके द्वारा सहदायिकी स्वामित्व के साथ धारित की जाएगी और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी संपत्ति मानी जाएगी जिसका उसके द्वारा वसीयती निपटान द्वारा निपटान किया जा सकता है।

(3) जहां हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ के बाद किसी हिंदू की मृत्यु हो जाती है, मिताक्षरा विधि द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में उसका हित, इस अधिनियम के तहत वसीयतनामा या बिना वसीयत के उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित होगा, न कि उत्तरजीविता द्वारा, और सहदायिक संपत्ति को इस प्रकार विभाजित माना जाएगा मानो विभाजन हुआ हो और,- (क) पुत्री को वही हिस्सा आवंटित किया जाता है जो पुत्र को आवंटित किया जाता है; (ख) पूर्व-मृत पुत्र या पूर्व-मृत पुत्री का हिस्सा, जैसा उन्हें विभाजन के समय जीवित रहने पर मिलता, ऐसे पूर्व-मृत पुत्र या ऐसी पूर्व-मृत पुत्री की जीवित संतान को आवंटित किया जाएगा; और (ग) पूर्व मृत पुत्र या पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत संतान का हिस्सा, जो उस संतान को मिलता यदि वह विभाजन के समय जीवित होती, पूर्व मृत पुत्र या पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत संतान को, जैसा भी मामला हो, आवंटित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी हिंदू मिताक्षरा सहदायिक का हित संपत्ति में वह हिस्सा समझा जाएगा जो उसे आबंटित किया गया होता यदि संपत्ति का विभाजन उसकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ होता, भले ही वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं।

(5) इस धारा में निहित कोई भी बात उस विभाजन पर लागू नहीं होगी जो दिनांक 20 दिसम्बर, 2004 से पहले किया गया हो।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए "विभाजन" से पंजीकरण अधिनियम, 1908 (16/1908) के अधीन विधिवत् पंजीकृत विभाजन विलेख के निष्पादन द्वारा किया गया कोई विभाजन या न्यायालय की डिक्री द्वारा किया गया विभाजन अभिप्रेत है।"

23. वर्तमान वाद धारा 6 में 2005 के संशोधन से पहले संस्थित किया गया था, तथा बक्शी राम की मृत्यु उससे भी पहले हुई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस न्यायालय के *भरत सिंह (पूर्वोक्त)* के निर्णय पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि वर्ष 2005 का संशोधन पूर्वव्यापी नहीं था। *भरत सिंह* मामले में, इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अभिनर्धारित किया कि:

"संशोधन अधिनियम 2005 को पूर्वव्यापी रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि संशोधन अधिनियम को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि संशोधन

अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले जो उत्तराधिकार हुए थे, उन्हें बदला नहीं जा सकता है।"

24. हालाँकि, इस स्थिति को धारा 6(1) और धारा 6(5) के प्रावधानों के मद्देनजर योग्य माना जाना चाहिए। धारा 6(1) के प्रावधानों में दर्ज है:

"इस उपधारा में निहित कोई भी बात दिनांक 20 दिसंबर, 2004 से पहले हुए संपत्ति के विभाजन या वसीयती निपटान सहित किसी भी निपटान या अलगाव को प्रभावित या अमान्य नहीं करेगी।"

25. इसी प्रकार, धारा 6(5) में उल्लेख है कि

"इस धारा में निहित कोई भी बात उस विभाजन पर लागू नहीं होगी जो दिनांक 20 दिसंबर, 2004 से पहले किया गया हो।"

इस प्रकार, वर्ष 2005 का संशोधन अधिनियम स्पष्ट है कि एचयूएफ की महिला सदस्यों के नव निर्मित हिस्साो ं को सहदायिकता में शामिल करने के लिए संपत्ति के किसी भी पिछले विभाजन या वसीयतनामा निपटान को प्रभावित या फिर से खोला नहीं जाना चाहिए। संसद का इरादा पिछले पारिवारिक समझौते को पुनः खोलकर अराजकता पैदा करना नहीं था, बल्कि यह इंगित करना था कि भविष्य की सभी कार्रवाइयों के लिए, उत्तरजीविता के नियम नहीं, बल्कि उत्तराधिकार के नियम डिफ़ॉल्ट रूप से संचालित होंगे और इसके अलावा, महिला सदस्य अपने पुरुष समकक्षों के समान ही हिस्सेदारी पाने की हकदार होंगी। हालांकि, समान रूप से, संशोधन अधिनियम स्पष्ट करता है कि धारा 6 के

संदर्भ में *'विभाजन' का क्या अर्थ है, अर्थात् "पंजीकरण अधिनियम, 1908 (16/1908) के तहत विधिवत पंजीकृत विभाजन के कार्य के निष्पादन द्वारा किया गया कोई भी विभाजन या न्यायालय के आदेश द्वारा किया गया विभाजन।"* तदनुसार, केवल वे विभाजन जो विधिवत पंजीकृत विभाजन विलेख के निष्पादन द्वारा किए गए हैं या न्यायालय के आदेश द्वारा किए गए विभाजन, अर्थात् धारा 6 द्वारा वैध माने गए विभाजन, जो निर्धारित कट-ऑफ तिथि से पहले हुए हैं, संशोधित धारा 6 के संचालन से बच जाते हैं, जो यदि प्रभावी होती है, तो एचयूएफ के भीतर हिस्साों के पुनर्वितरण की आवश्यकता होगी। धारा 6 में 'विभाजन' की अभिव्यक्ति को परिभाषित करने के बाद, संसद ने स्पष्ट किया कि संशोधन से कौन से विभाजन अप्रभावित रह गए हैं, और कौन से विभाजन इस विधि में इस परिवर्तन के लिए अतिसंवेदनशील हैं, जिससे न्यायालयों को इस संबंध में स्पष्ट और सुस्पष्ट निर्देश मिल गए हैं। इस प्रकार, यदि धारा 6(5) के स्पष्टीकरण के तहत परिकल्पित विभाजन दिनांक 20.12.2004 से पहले हुआ है, तो ही न्यायालय संशोधित धारा 6 को अनदेखा कर सकते हैं।

26. महत्वपूर्ण रूप से, चूंकि पक्षकारों के अधिकार और हिस्सा विभाजन की तिथि के अनुसार तय किए जाते हैं, अतः विभाजन की तिथि निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। सबसे *पहले,* जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, यह धारणा कि एक विभाजन एक पुरुष सदस्य की मृत्यु की तिथि को होता है, और उस समय

निहित अधिकारों में विभाजित हो जाता है, जैसा कि एकल न्यायाधीश द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, सही दृष्टिकोण नहीं है। वह घटना (अर्थात् मृत्यु) केवल यह निर्धारित करती है कि उस व्यक्ति के हिस्से को परिवार के सदस्यों के बीच कैसे विभाजित किया जाएगा (या तो उत्तरजीविता या उत्तराधिकार द्वारा), बजाय इसके कि परिवार की संपत्ति में कोई व्यापक-आधारित परिवर्तन किया जाए या एक विभाजन को प्रभावित किया जाए जो परिवार संरचना में बाद के परिवर्तनों या विधि में परिवर्तनों के खिलाफ होगा। *दूसरा,* न तो यह प्रस्ताव कि विभाजन के वाद दायर करने के समय हिस्साों को परिभाषित किया गया है, सही है। बल्कि, एचयूएफ, और विशेष वाद से, सह-पक्षकार, वाद दायर करने के बाद भी जारी रहता है। अपने आप में वाद दायर करने का मतलब यह नहीं है कि विभाजन हुआ है, जब तक कि न्यायालय का आदेश विभाजन को प्रभावित नहीं करता है, या विभाजन के पंजीकृत विलेख पर पक्षकारों के बीच हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं। तदनुसार, वाद विचाराधीन रहने के दौरान परिवार के सदस्यों की मृत्यु या जन्म स्पष्ट वाद से विभाजन में हिस्साों को प्रभावित करेगा। इसी तरह, वाद विचाराधीन रहने के दौरान विधी में कोई भी बदलाव, उदाहरण के लिये वाद एचएसए की खंड 6 के मामले में, पक्षकारों के अंतिम हिस्साों को प्रभावित करेगा। एक विपरीत निष्कर्ष न केवल धारा 6(5) में 'विभाजन' की परिभाषा के विपरीत होगा, बल्कि इसका अर्थ यह भी होगा, उदाहरण के लिये

वाद का कोई भी विभाजन वाद दायर किए जाने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता है, एक प्रस्ताव जिसे विभिन्न अवसरों पर खारिज कर दिया गया है।

27. वास्तव में, इस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय ने *गंडूरी कोटेश्वरम्मा व अन्य बनाम चाकिरी यानाडी व अन्य,* 2011 (12) एससीआर 968 में विचार किया है। इसमें, वर्ष 2005 के संशोधन से पहले पारिवारिक विभाजन हेतु एक वाद दायर किया गया था, तथा इसके अलावा, दिनांक 19.03.1999 तथा दिनांक 27.09.2003 को विचारण न्यायालय द्वारा दो प्रारंभिक डिक्री पारित की गई थीं, जिसमें पक्षकारों के हिस्साोंं का संकेत दिया गया था। तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था:

> *धारा 6 की उपधारा (5) में संलग्न स्पष्टीकरण में निहित स्पष्ट प्रावधान के आलोक में, धारा की गैर-अनुप्रयोज्यता का निर्धारण करने के लिए, यह पता लगाना प्रासंगिक है कि क्या विभाजन दिनांक 20 दिसंबर, 2004 से पहले पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत विधिवत पंजीकृत विभाजन विलेख या न्यायालय के आदेश द्वारा किया गया है। वर्ष 2005 के संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1956 के अधिनियम में लाई गई धारा 6 के संदर्भ में उपरोक्त विधिक स्थिति की पृष्ठभूमि में, हमें जिस प्रश्न का उत्तर देना है, वह यह है कि क्या दिनांक 19 मार्च, 1999 को विचारण न्यायालय द्वारा पारित और दिनांक 27 सितंबर, 2003 को संशोधित प्रारंभिक डिक्री अपीलार्थीगण को दिनांक 2005 के संशोधन अधिनियम के लाभों से वंचित करती है, हालांकि विभाजन के लिए अंतिम डिक्री अभी तक पारित नहीं हुई है।*

28. इस प्रश्न का उत्तर देते हुए न्यायालय ने कहा कि न तो वाद दायर करना और न ही प्रारंभिक डिक्री संशोधित धारा 6 के अर्थ में विभाजन का गठन करती है। इस प्रकार, नव निर्मित अधिकार पक्षकारों को उपलब्ध होंगे। विशेष रूप से, न्यायालय ने उल्लेख किया:

> *"16. कानूनी स्थिति यह तय है कि संयुक्त हिंदू परिवार का विभाजन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, इनमें से दो तरीके हैं (एक) विभाजन के पंजीकृत दस्तावेज द्वारा और (दो) न्यायालय के आदेश द्वारा। वर्तमान मामले में, बेशक, विभाजन दिनांक 20 दिसंबर, 2004 से पहले पंजीकृत विभाजन दस्तावेज या न्यायालय के आदेश द्वारा नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा दायर विभाजन के वाद में एकमात्र चरण दिनांक 19 मार्च, 1999 की प्रारंभिक डिक्री के अनुसार हिस्साों का निर्धारण है, जिसे दिनांक 27 सितंबर, 2003 को संशोधित किया गया और आयुक्त की रिपोर्ट प्राप्त हुई।*
>
> *17. प्रारंभिक डिक्री पक्षकारों के अधिकारों और हितों को निर्धारित करती है। प्रारंभिक डिक्री पारित करके विभाजन के लिए वाद निपटाया नहीं जाता है। अंतिम डिक्री द्वारा संयुक्त हिंदू परिवार की अचल संपत्ति को सीमाओं के अनुसार विभाजित किया जाता है। प्रारंभिक डिक्री पारित होने के बाद, अंतिम डिक्री पारित होने तक वाद जारी रहता है। यदि अंतराल में अर्थात् प्रारंभिक डिक्री पारित होने के बाद और अंतिम डिक्री पारित होने से पहले, ऐसी घटनाएँ और परिस्थितियाँ घटित होती हैं, जिससे हिस्साों में बदलाव की आवश्यकता होती है, तो न्यायालय के लिए प्रारंभिक डिक्री में*

संशोधन करने या बदली हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों के अधिकारों और हितों को पुनः निर्धारित करने के लिए एक और प्रारंभिक डिक्री पारित करने में कोई बाधा नहीं है।"

29. इससे पहले, *एस. साई रेड्डी बनाम एस. नारायण रेड्डी व अन्य,* (1991) 3 एससीसी 647 में, सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रश्न यह था कि क्या धारा 29क (एचएसए में राज्य संशोधन द्वारा) को शामिल करने का मतलब यह है कि एचयूएफ में अविवाहित बेटियाँ अपने भाइयों के बराबर हिस्से की हकदार होंगी, विचारण न्यायालय के प्रारंभिक निर्णय के बाद, और इसके खिलाफ अपील उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। विचारण न्यायालय ने यह कहते हुए दावे को खारिज कर दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज किए जाने के साथ, प्रारंभिक निर्णय अंतिम हो गया था और बहनें इसे अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने की हकदार नहीं थीं। उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को उलट दिया, तथा सहमति जताते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"... हालांकि, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि संशोधित प्रावधान के उद्देश्यों के लिए विभाजन कब प्रभावी माना जा सकता है। संयुक्त हिंदू परिवार का विभाजन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जैसे पारिवारिक समझौते से, विभाजन के पंजीकृत दस्तावेज से, पक्षकारों द्वारा मौखिक व्यवस्था से या न्यायालय के आदेश से,

चूंकि यह कानून लाभकारी है और महिलाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इसे कानून की किताब में शामिल किया गया है, जो

समाज के सभी स्तरों पर एक कमजोर वर्ग है, अतः इसे उदार प्रभाव देना आवश्यक है। इस कारण से भी, हम वर्तमान मामले में विधायिका के मन में विभाजन की अवधारणा को संयुक्त परिवार की स्थिति को अलग करने के मात्र एक मात्र प्रयास से समान नहीं मान सकते हैं, जो परिवार के किसी सदस्य द्वारा ऐसा करने की मात्र इच्छा व्यक्त करने से प्रभावित हो सकता है। वर्तमान मामले में विधायिका के मस्तिष्क में जो विभाजन है, वह निस्संदेह सभी मामलों में पूर्ण विभाजन है और जिसने एक अपरिवर्तनीय स्थिति उत्पन्न की है। एक प्रारंभिक डिक्री जो केवल उन हिस्साोंं की घोषणा करता है जो स्वयं परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, कोई अपरिवर्तनीय स्थिति उत्पन्न नहीं करती है। अतः, हमारा विचार है कि जब तक संपत्ति का विभाजन माप और सीमांकन द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तब तक बेटियों को अधिनियम द्वारा प्रदत्त लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता है।

30. अतः सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वर्ष 1956 के अधिनियम द्वारा बेटियों के पक्ष में बनाए गए अधिकार प्रभावी होंगे, भले ही विचारण न्यायालय ने अधिनियम के पारित होने से पहले एक प्रारंभिक डिक्री दी थी, क्योंकि अंतिम अधिकार निर्धारित किए जाते हैं और विभाजन केवल एक अंतिम डिक्री द्वारा से किया जाता है। 'विभाजन' की विशिष्ट परिभाषा के पीछे का तर्क-जैसा कि उपरोक्त उद्धरण से स्पष्ट है-यह है कि केवल ऐसे विभाजन पर विचार किया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप अपरिवर्तनीय स्थिति हो। अन्य सभी मामलों में, धारा 29क के लाभकारी उद्देश्य को देखते

हुए-और इसमें, हिंदू महिलाओं के पक्ष में सृजित संशोधित खंड 6 के अधिकारों को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। न तो विभाजन का वाद दायर करना, न ही एचयूएफ के किसी सदस्य द्वारा मौखिक बयान, और निश्चित वाद से एक मानित विभाजन (केवल मृतक के अधिकारों को निर्धारित करने के लिए सीमित प्रभाव के लिए बनाया गया) जैसी कोई अपरिवर्तनीय स्थिति पैदा नहीं करता है।

31. यह प्रश्न हाल ही में *प्रेमा बनाम नांजे गौड़ा एवं अन्य,* 2011 (6) स्केल 28 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी आया था। उस मामले में, परिवार के एक पुरुष सदस्य ने वर्ष 1989 में बंटवारे के लिए वाद दायर किया था, जिस पर वर्ष 1992 में निर्णय सुनाया गया था। उच्च न्यायालय में प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ महिला उत्तराधिकारी की अपील वर्ष 1999 में खारिज कर दी गई। इस बीच, वादी ने वर्ष 1999 में अंतिम डिक्री कार्यवाही शुरू की थी, जिसमें प्रतिवादी (महिला उत्तराधिकारी) ने कर्नाटक में वर्ष 1994 में धारा 6क, एचएसए में संशोधन को देखते हुए संपत्ति में बढ़े हुए हिस्से की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, अर्थात् वाद और प्रारंभिक डिक्री के संस्थित होने के बाद विचारण न्यायालय ने इस आधार पर आवेदन खारिज कर दिया कि धारा 6क का प्रभाव पूर्वव्यापी नहीं था। *साई रेड्डी* (पूर्वोक्त) के निर्णय पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में समवर्ती निष्कर्षों को पलट दिया:

> *"अतः, प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा शुरू किए गए वाद की कार्यवाही को संयुक्त परिवार की संपत्तियों के वास्तविक विभाजन के संबंध में*

अंतिम नहीं माना जा सकता है तथा फूलचंद बनाम गोपाललाल (पूर्वोक्त) और एस.साई रेड्डी बनाम एस. नारायण रेड्डी (पूर्वोक्त) में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुये, अपीलार्थी के लिए संयुक्त परिवार की संपत्तियों में अपने हिस्से में वृद्धि का दावा करना स्वतंत्र था क्योंकि उसने कर्नाटक अधिनियम संख्या 23/1994 के लागू होने तक शादी नहीं की थी। कर्नाटक अधिनियम संख्या 23/1994 की धारा 6क आंध्र प्रदेश अधिनियम की धारा 29क के समान है। अतः, कोई कारण नहीं है कि एस. साई रेड्डी बनाम एस. नारायण रेड्डी (पूर्वोक्त) में दिए गए निर्णय के अनुपात को संयुक्त परिवार के पुरुष सदस्यों के बराबर हिस्सा देने के अपीलार्थी के दावे पर निर्णय लेने के लिए लागू नहीं किया जाना चाहिए...

14. हम यह भी जोड़ सकते हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रारंभिक डिक्री के आधार पर, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने की थी, उसमें तय किए गए मुद्दे अंतिम माने जाएंगे, लेकिन चूंकि विभाजन के वाद का निर्णय चरणों में किया जाना आवश्यक है, <u>अतः इसे तभी पूरी तरह से तय माना जा सकता है जब अंतिम डिक्री पारित हो जाए। यदि इस अंतराल में विभाजन के वाद में किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, तो उसका हिस्सा जीवित पक्षकारों को आवंटित किया जाना आवश्यक है और यह अंतिम डिक्री कार्यवाही में किया जा सकता है। इसी तरह, यदि अंतिम डिक्री कार्यवाही के समापन से पहले पक्षकारों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन किया जाता है, तो ऐसे संशोधन से लाभान्वित पक्षकार न्यायालय से संशोधन का संज्ञान लेने और उसे प्रभावी</u>

<u>करने का अनुरोध कर सकता है।</u> यदि वाद में पक्षकारों के अधिकार अन्य कारणों से बदल जाते हैं, <u>तो अंतिम डिक्री कार्यवाही समाप्त करने वाला न्यायालय न केवल ऐसे परिवर्तन का नोटिस लेने और उचित आदेश पारित करने का हकदार है,</u> बल्कि उसका कर्तव्य भी है।"
(जोर दिया गया)

32. साई रेड्डी (पूर्वोक्त), *गंडूरी कोटेश्वरम्मा* (पूर्वोक्त) *और प्रेमा* (पूर्वोक्त) के निर्णयों से यह स्पष्ट है कि हिंदू संयुक्त परिवार का विभाजन – जो प्रत्येक सदस्य के हित को स्पष्ट करता है, तथा इस प्रकार हितों को कानून में आगे के परिवर्तनों के प्रति प्रतिरक्षित बनाता है – केवल एचएसए द्वारा निर्धारित तरीके से हो सकता है। एचएसए की धारा 6 के प्रावधान के तहत समझा गया विभाजन वास्तविक विभाजन नहीं है जो एचयूएफ के सभी सदस्यों के हित को स्पष्ट करता है, बल्कि यह केवल विधायिका द्वारा यह निर्धारित करने के लिए पेश किया गया एक विधिक निर्माण है कि यदि वर्ग I की महिला रिश्तेदार जीवित है तो मृतक के हित उसके उत्तराधिकारियों को कैसे प्राप्त होंगे। समझे गए विभाजन की इस कल्पना का उद्देश्य (अन्यथा उत्तरजीविता के सरल नियम का पालन करने के विपरीत) यह है कि वर्ग I की महिला उत्तराधिकारियों को भी मृतक पुरुष की सहदायिक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त होता है यह तर्क देना कि इस तरह का समझा हुआ बंटवारा अंततः बेटियों के हित को स्पष्ट करता है और बाद में उन्हें मिलने वाले कोई भी अधिकार जो सहदायिक संपत्ति में हित प्रदान

करते हैं, वे लागू नहीं किए जा सकते, धारा 6 के प्रावधान की शर्तों और भावना के विपरीत है जो वर्ष 2005 के संशोधन और संशोधन पत्र के पहले मौजूद थे। साई रेड्डी (पूर्वोक्त), प्रेमा (पूर्वोक्त) और गंडूरी कोटेश्वरम्मा (पूर्वोक्त) सभी ने लगातार यह माना है कि महज स्थिति में विच्छेद, जो कि बंटवारे के मुकदमे की संस्था द्वारा लाया जाना चाहता है, अपरिवर्तनीय हिस्साों में परिणत नहीं होता है। इन निर्णयों में *फूलचंद एवं अन्य बनाम गोपाल लाल* एआईआर 1967 एससी 1470 में एक पुराने निर्णय (प्रिवी काउंसिल) का भी संज्ञान लिया गया और यहां तक कि *जदुनाथ रॉय व अन्य बनाम परमेश्वर मलिक व अन्य, एआईआर 1940 पीसी 11,* जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि विभाजन के वाद में प्रारंभिक डिक्री के बाद भी, न्यायालय न केवल शक्तिहीन है, बल्कि उसका यह कर्तव्य है कि वह बाद के घटनाक्रमों को प्रतिबिंबित करे, जिससे सहदायिक या संयुक्त परिवार में उतार-चढ़ाव के कारण (पक्षकारों) हिस्साों का पुन-समायोजन आवश्यक हो सकता है।

33. दूसरे और ज़्यादा बुनियादी नज़रिए से, अगर बख्शी राम की वर्ष 1960 में मृत्यु के बाद और उनके बेटों और बेटियों के बीच उनके हित के बंटवारे के बाद पुरुष सहदायिकों (भाइयों) के बीच हितों में उतार-चढ़ाव जारी रहा, तो ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि बेटी के हित को जब्त कर लिया जाए। वे एचयूएफ के सदस्य बने रहे (हालाँकि सहदायिक नहीं), और इस तरह परिवार की महिला सदस्यों के रूप में उनके पक्षकार में अर्जित किसी भी अधिकार का लाभ उठाने

के हकदार हैं, खास तौर पर इस मामले में वर्ष 2005 का संशोधन इस मामले में, आज तक कोई अंतिम डिक्री पारित नहीं हुई है, और न ही किसी पंजीकृत विभाजन विलेख को अभिलेख पर रखा गया है या किसी भी पक्षकार द्वारा उस पर भरोसा किया गया है। तदनुसार, एचएसए की संशोधित धारा 6 लागू होती है। अतः, इस पहलू पर विद्वान एकल न्यायाधीश के तर्क और निष्कर्ष कायम नहीं रह सकते है। इसी तरह, *प्रेमा* (पूर्वोक्त) और *गंडूरी कोटेश्वरम्मा* (पूर्वोक्त) के मद्देनजर, भारत सिंह (एक विद्वान एकल न्यायाधीश) में तर्क और निर्णय को अब सुव्यवस्थित विधि नहीं माना जाता है। तदनुसार उक्त निर्णय को निरस्त किया जाता है।

34. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, न्यायालय को अब संबंधित विभिन्न संपत्तियों में पक्षकारों के हिस्से का निर्धारण करना चाहिए। बख्शी राम की मृत्यु से शुरू होने वाले घटनाक्रम को संबोधित करने से पहले, यह याद रखना आवश्यक है कि सुदर्शन लाल की मृत्यु बिना किसी महिला वर्ग I वारिस के निःसंतान हुई थी, और इस प्रकार, उनके निधन पर, असंशोधित धारा 6 के तहत उत्तरजीविता का नियम लागू हुआ, और सहदायिक संपत्ति शेष सहदायिकों, उनके पिता बख्शी राम और दो भाइयों के बीच पुनर्वितरित की गई। इसके बाद, वर्ष 1960 में बख्शी राम की मृत्यु पर, क्योंकि उनके बाद उनकी विधवा और पांच बेटियाँ (एचएसए की अनुसूची के तहत वर्ग I वारिस) बची थीं, असंशोधित धारा 6 के प्रावधान, जैसा कि उस समय लागू था, लागू हुये। तदनुसार, यदि एक माना

हुआ विभाजन होता, तो बख्शी राम, उनके दो जीवित बेटे, कुलभूषण लाल और मदन मोहन शर्मा को सहदायिक संपत्ति में से प्रत्येक को 1/3 हिस्सा मिलता। बख्शी राम की मृत्यु, और हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 की धारा 3 के प्रभाव को देखते हुए (धारा 14, एचएसए के साथ पढ़ें, जो अधिनियम 1937 द्वारा दी गई जीवन संपदा को पूर्ण हित बनाती है), बख्शी राम, दोनों बेटों और चनन देवी प्रत्येक को 1/4 हिस्सा प्राप्त होता। बख्शी राम का 1/4 हिस्सा, फिर, धारा 8 के साथ पठित प्रावधान के संदर्भ में, उनके वर्ग I उत्तराधिकारियों को 8 भागों में समान रूप से प्राप्त होता है, अर्थात् उनकी पत्नी, और 7 जीवित बच्चे। इस प्रकार, 7 जीवित बच्चों को 1/32 हिस्सा मिला, और चमन देवी को 9/32 (अर्थात् 1/4 प्लस 1/32) हिस्सा मिला। बख्शी राम की मृत्यु के बाद अविभाजित सहदायिक हिस्से के शेष 1/2 में से, 2 जीवित पुरुष सदस्यों ने इसे समान रूप से साझा किया, इसके बाद, एचएसए की धारा 15(1) के अनुसार, चनन देवी की मृत्यु पर उनका 9/32 हिस्सा उनके 7 जीवित बच्चों को समान अनुपात में मिला, अर्थात् प्रत्येक के पास 9/224 हिस्सा था। फिर, 2005 के संशोधन के पारित होने के साथ, 5 बेटियों में से प्रत्येक ने 2 पुरुष सदस्यों के साथ सहदायिक में हिस्सा हासिल कर लिया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सहदायिक में शेष हिस्सा 1/2 था, और इस प्रकार, 7 सदस्यों में से प्रत्येक के पास सहदायिक के रूप में 1/14 हिस्सा है, जिसे इस वाद के आधार पर अब विभाजित करने की मांग की गई है।

संक्षेप में, पक्षकारों के हिस्सा इस प्रकार हैं: बख्शी राम की मृत्यु से उत्तराधिकार के रूप में प्रत्येक को 1/32 हिस्सा, चनन देवी से उत्तराधिकार के रूप में प्रत्येक को 9/224 हिस्सा और सहदायिक के रूप में प्रत्येक को 1/14 हिस्सा इस प्रकार, 7 बच्चों में से प्रत्येक का हिस्सा 1/32 प्लस 9/224 प्लस 1/14 है, जो 1/7 के बराबर है। दूसरे शब्दों में, 7 व्यक्तियों में से प्रत्येक का सहदायिक संपत्तियों में बराबर हिस्सा है।

35. इस स्थिति में, न्यायालय को यह भी विचार करना चाहिए कि जिन संपत्तियों को अपीलार्थी ने एचयूएफ का हिस्सा बताया है, वास्तव में वे कौन सी हैं। अपीलार्थी ने संपत्तियों को एचयूएफ का हिस्सा होने का दावा किया है, जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में दिखाया गया है। विभाजन के बाद पुनर्वास मंत्रालय द्वारा भुगतान किए गए मुआवजे से संबंधित दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि उस समय एक एचयूएफ अस्तित्व में था। इसके अलावा, दिनांक 1 अप्रैल, 1968 की साझेदारी विलेख और रि.या.(सि.) 1921/1986 में कथन दोनों प्रतिवादीगण के इस दावे का खंडन करते हैं कि कोई एचयूएफ नहीं था। वास्तव में, एचयूएफ के विभाजन या बाद में किसी भी समय संपत्तियों के विभाजन को प्रदर्शित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया। हालांकि, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने *डी.एस. लक्ष्मैया व अन्य बनाम एल. बालासुब्रमण्यम व अन्य,* 2003 (7) स्केल 1 में उल्लेख किया है:

"9.....संयुक्त परिवार के अस्तित्व का प्रमाण इस धारणा पर भार नहीं डालता कि परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गई संपत्ति संयुक्त है, तथा इस तथ्य को स्थापित करने का भार किसी भी व्यक्ति पर है जो यह दावा करता है कि संपत्ति की कोई भी वस्तु संयुक्त है....."

वाद में वादी और अपीलार्थी ने निम्नलिखित संपत्तियों के अलावा किसी भी संपत्ति के संबंध में इस दायित्व का निर्वहन नहीं किया है, जिन्हें प्रतिवादीगण की स्वीकृति के अनुसार एचयूएफ का हिस्सा माना गया है: (क) खसरा संख्या 2609/727-728 वाला एक प्लॉट, जो तुगलकाबाद, तहसील महरौली, दिल्ली में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 5 बीघा, 1 बिस्वा है, (ख) खसरा संख्या 32/28/1 व 32/28/2 वाला एक प्लॉट, जिसका क्षेत्रफल 2 बीघा, 5 बिस्वा है, (ग) खसरा संख्या 231 वाला एक प्लॉट, जिसका क्षेत्रफल 2 बीघा, 13 बिस्वा है, जो ताजपुल गांव, तहसील महरौली, जिला दिल्ली में है, (घ) खसरा संख्या 36/28/2 व 36/29/2 वाला एक प्लॉट, जिसका क्षेत्रफल 15 बिस्वा है तदनुसार, इस न्यायालय को विद्वान एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला। हालाँकि, इन 5 संपत्तियों में से, जोशी रोड पर स्थित घर के अधिकार सुदर्शन लाल के पक्ष में छोड़ दिए गए थे, और खसरा संख्या 32/28/1 और 32/28/2 वाले प्लाट को दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 51 के तहत उत्तराधिकार के नियमों द्वारा शासित माना गया था, जो केवल परिवार के पुरुष सदस्यों को उत्तराधिकार प्रदान करता

है, इस प्रकार यहाँ अपीलकर्ता को बाहर रखा गया है। अंत में, शेष संपत्तियों के संबंध में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि भूमि सुधार अधिनियम की धारा 185 उस अधिनियम द्वारा विनियमित संपत्तियों के संबंध में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता को रोकती है, अतः कोई डिक्री नहीं दी जा सकती है।

36. करोल बाग के घर के त्याग के संबंध में, अपीलार्थी ने सुनवाई के दौरान जोशी रोड पर घर में हिस्सेदारी के संबंध में उसके और चौथे प्रतिवादी द्वारा निष्पादित त्याग विलेख की प्रमाणित प्रति को सुदर्शन लाल के पक्ष में स्वीकार किया। यद्यपि यह कहा गया था कि यह दस्तावेज एक मुख्तारनामा माना जाता था, न कि त्याग विलेख, पंजीकृत दस्तावेज को खराब करने के लिए धोखाधड़ी या जबरदस्ती की कोई दलील नहीं दी गई है, तथा इस प्रकार, न्यायालय को विद्वान एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला है।

37. अंतत, इस न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या ऊपर उल्लिखित संपत्तियों को दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 185 के प्रावधानों के प्रकाश में विभाजित किया जा सकता है, जो अधिनियम द्वारा विनियमित संपत्तियों से संबंधित मामलों के संबंध में सिविल न्यायालयों के अधिकारिता पर रोक लगाता है:

> *"185. इस अधिनियम के तहत वाद आदि का संज्ञान - (1) इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत प्रदान की गई व्यवस्था के अलावा, अनुसूची I के कॉलम 7 में उल्लिखित न्यायालय के अलावा कोई भी न्यायालय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, कॉलम 3 में उल्लिखित किसी भी वाद, आवेदन या कार्यवाही का संज्ञान नहीं लेगा।*

इसके अलावा, धारा 51 इस हद तक प्रासंगिक है कि यह एचएसए में निर्दिष्ट नियमों के विपरीत, अधिनियम द्वारा शासित संपत्तियों के लिए उत्तराधिकार की एक अलग स्थिति उत्पन्न करती है।

38. इस मुद्दे के निष्कर्ष के संबंध में कि क्या खसरा संख्या 32/28/1 व 32/28/2 वाले प्लाट को भूमि सुधार अधिनियम की धारा 51 के तहत या एचएसए के तहत माना जाना चाहिए, और क्या शेष तीन संपत्तियों को भी इसी तरह दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के तहत निपटाया जाना चाहिए, यह न्यायालय नोटिस करता है कि सभी चार संपत्तियां महरौली, तुगलकाबाद और बदरपुर में स्थित हैं। इन सभी क्षेत्रों को दिल्ली नगर निगम ("दि.न.नि.") द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 507 के तहत अधिसूचना एफ.9(2)/66/लॉ/कॉर्प दिनांक 28.05.1966 (बदरपुर और तुगलकाबाद) और दिनांक 13.06.1962 (महरौली) के माध्यम से "शहरीकृत गांवों" के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र नहीं माना जाता है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि यदि ऐसा होता भी है, तो भी इन क्षेत्रों में स्थित संपत्तियां दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के तहत विनियमित होती

रहेंगी। इस प्रकार, यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई भूमि, चाहे वह शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में हो, जैसा कि दि.न.नि. द्वारा निर्धारित किया गया है, कृषि भूमि बनी रहेगी और इस प्रकार, दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगी।

39. इस मामले पर इस न्यायालय द्वारा पहले भी विचार किया जा चुका है। *त्रिखा राम बनाम साहिब राम,* 69 (1997) डीएलटी 749 में विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि जहां कोई क्षेत्र दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 507 के तहत अधिसूचना के तहत शहरीकृत है, वहां दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इस निर्णय के बाद *माधो प्रसाद बनाम श्री राम किशन और अन्य,* 2001 (7) एडी (दिल्ली) 72 में एक अन्य एकल न्यायाधीश ने निर्णय दिया। हालांकि, रि.या.(सि.) सं. 4143/2003, दिनांक 25.08.2004 में विपरीत राय दिए जाने के कारण, मामले को इस न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ को *श्रीमती इंदु खोराना बनाम ग्राम सभा व अन्य,* एमएएनयू/डीई/0969/2010 के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में भेजा गया, जहां संदर्भ का स्पष्ट रूप से निम्नलिखित शब्दों में उत्तर दिया गया:

> *"11. इस प्रकार हम मानते हैं कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 507(क) के तहत अधिसूचना जारी करके एक बार ग्रामीण क्षेत्र को शहरीकृत कर दिया जाता है, तो*

दिल्ली सुधार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। संदर्भ का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।"

40. बाद में उस निर्णय को चुनौती दी गई और नारायण सिंह व अन्य बनाम वित्त आयुक्त व अन्य, ले.पे.अ. सं. 591/2008, दिनांक 22.11.2012 के निर्णय में एक वृहद न्यायपीठ को भेजा गया, जहां इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने *इंदू खोराना* (पूर्वोक्त) के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए कहा कि "डीएमसी अधिनियम की धारा 507(क) के तहत अधिसूचना का मूल उद्देश्य भूमि को कृषि से शहरी में परिवर्तित करना है।" इन सुसंगत निष्कर्षों के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि इस मामले में धारा 507 के तहत अधिसूचना का प्रभाव चार संपत्तियों को दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के दायरे से हटाना था क्योंकि अधिनियम की विषय-वस्तु शहरी भूमि की बजाय ग्रामीण कृषि संपत्तियां हैं। तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि विचाराधीन चार संपत्तियां ऊपर निर्दिष्ट शेयर अनुपात में अपीलार्थी को हस्तांतरित नहीं होनी थीं, अपास्त किए जाने योग्य है।

41. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों एवं निर्णय को अपास्त किया जाता है। इस वाद को कानून के अनुसार, माप और सीमांकन के माध्यम से संपत्तियों के विभाजन को आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। रोस्टर आवंटन के अनुसार वाद को संबंधित न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, जो पक्षकारों को नोटिस जारी करने के बाद मामले में

आगे की कार्यवाही करेंगे। उपरोक्त शर्तों के तहत अपील स्वीकार की जाती है। जुर्माने के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

एस. रवींद्र भट्ट
(न्यायाधीश)

नज्मी वज़ीरी
(न्यायाधीश)

31 जनवरी 2014

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*